उमा प्रचार

वर्ष 15, अंक 53

अप्रैल–जून 2011

जम्मू–कश्मीर में जमीनी लोकतंत्र की गूंज
संपादकीयः पंचायती राज अपडेट

आशा ने जगाई आशा
नवभारत टाइम्स से साभार

ब्रिटेन से आया एमबीए सरपंच
नवभारत टाइम्स से साभार

महिला राजनीतिक सशक्तीकरण दिवस समारोह
पंचायत समाचार

केवल निजी वितरण के लिए

यह अंक

जम्मू–कश्मीर में लगभग दस वर्ष बाद पंचायती राज चुनाव हुए हैं। तमाम कठिन और विपरीत परिस्थितियों के बाद मतदाताओं की 80 प्रतिशत भागीदारी और छिटपुट हिंसा को छोड़कर लगभग शांतिपूर्ण चुनाव होना आश्चर्य की बात है। जम्मू–कश्मीर का यह चुनाव परिणाम ऐसे राज्यों के लिए एक उदाहरण भी है, जहां मतदान का प्रतिशत बहुत कम रहता है।

इन चुनावों से यह स्पष्ट हो गया है कि यहां की जनता पंचायती राज के जरिए अपने क्षेत्र का विकास चाहती है।

लंबे समय से अशांत वातावरण में जी रहे इस राज्य में सुख–शांति कैसे आ सकती है – पढ़िए पंचायती राज अपडेट का संपादकीय।

वर्ष 2010 के विशिष्ट महिला पंचायत प्रतिनिधि पुरस्कार के लिए अरुणाचल जिला परिषद् की अध्यक्ष चैंगलैंग जुनपो और राजस्थान में राजसमंद जिले की विजयपुरा ग्राम पंचायत की सरपंच रुक्मणी देवी को चुना गया है। यह पुरस्कार उन्हें इंस्टीटयूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा 25–26 अप्रैल 2011 को आयोजित एक समारोह में दिया गया।

18वें महिला राजनीतिक सशक्तिकरण दिवस समारोह की जानकारी भी आपको मिलेगी।

इसके अलावा पंचायती राज संबंधित छोटे–मोटे समाचार भी यहां प्रस्तुत हैं।

जम्मू–कश्मीर में जमीनी लोकतंत्र की गूंज

जम्मू एवं कश्मीर अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए देश–विदेश में मशहूर है, लेकिन अब उसकी जनता ने पंचायत चुनाव के दौरान जमीनी लोकतंत्र की दिशा में एक नया इतिहास रचा है। कई टिप्पणीकार आतंकवादी खतरों और धमकियों की वजह से आशंका प्रकट कर रहे थे कि इन चुनावों का आयोजन एक अत्यंत कठिन चुनौती होगा और यदि चुनाव लगभग शांतिपूर्ण तरीके से हो भी गए तो इसमें वोटरों की उपस्थिति बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। 13 अप्रैल से 16 जून के दौरान सोलह चरणों में हुए पंचायतों के चुनाव ने तमाम आशंकाओं एवं भ्रांतियों को गलत साबित कर दिया और हिंसा की छिटपुट घटनाओं को छोड़कर कोई बड़ी वारदात नहीं हुई। आश्चर्यजनक बात यह है कि आतंकवाद से प्रभावित कई क्षेत्रों में लगभग 80 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। यह न सिर्फ शांति एवं कानून, बल्कि पंचायती राज संस्थाओं के जरिए विकास में जनता की आस्था का परिचायक है और देश के उन अन्य राज्यों के लिए एक सबक भी, जहां मतदान का प्रतिशत बहुत कम रहता है।

राज्य में पंचायतों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और उसमें जनता की बड़े पैमाने पर हिस्सेदारी से पता चलता है कि जमीनी स्तर पर कार्यरत पंचायती राज संस्थाओं के जरिए जनता अपना और अपने क्षेत्र का तेजी से विकास चाहती है। इससे पहले वर्ष 2000 में पंचायतों के चुनाव हुए थे, जिसमें अशांति और खूनखराबे के कारण जनता ने अधिक उत्साह नहीं दिखाया। कई पंचायतों के हजारों पद खाली रह गए क्योंकि लोगों ने चुनाव ही नहीं लड़ा। इसके बाद दस साल गुजर गए, जिसमें पंचायतों के चुनाव नहीं हुए। इस दौरान केंद्र सरकार ने मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम) और दूसरी अनेक जन–कल्याणकारी योजनाएं बनाईं, जिनका राज्य और उसकी जनता को फायदा नहीं पहुंचा क्योंकि इनकी धनराशि पंचायतों के जरिए दी जाती है।

ताजा पंचायत चुनावों में जनता ने विशाल संख्या में भाग लेकर स्थानीय स्वशासी निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों पर यह महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है कि वे अन्य नेताओं की तरह थोथी घोषणा न करें, बल्कि क्षेत्रीय विकास पर बल देकर कार्यों को ईमानदारी से पूरा करें। इन चुनावों में किसी प्रकार की सांप्रदायिक कटुता पैदा नहीं हुई और जनता ने भाईचारे का परिचय दिया। बारामूला जिले के एक गांव के मुस्लिम बहुल वार्ड से पंच के रूप में पंडित महिला उम्मीदवार आशा निर्वाचित हुई, जिससे कश्मीर के जमीनी स्तर पर सांप्रदायिक सौहार्द के बारे में पता चलता है। आशा को उसी के वार्ड के मुस्लिम मतदाताओं ने चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया और उसे समर्थन भी दिया। वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक लछीपुरा गांव में 27 वर्षीय एक नवजवान भारी मतों के साथ सरपंच चुना गया, जो पेशे से इंजीनीयर और मॉडल था, पर गांव के विकास के जज्बे के साथ अपनी मातृभूमि पर लौटा और जनता ने उसके ख्वाब को भरपूर समर्थन दिया। पाकिस्तान की सीमा से सटे कांग गांव में 28 वर्षीय एक एमबीए युवक गुरमीत सिंह बाजवा सरपंच चुना गया है। 2008 में भारत लौटे बाजवा ने ब्रिटेन के डर्बीशायर से एमबीए की डिग्री प्राप्त की है। ये दोनों घटनाएं यह भी साबित करती हैं कि आज के युवा अपने गांव और क्षेत्र के विकास के प्रति उदासीन नहीं हैं, बल्कि स्वयं पहल कर रुचि ले रहे हैं। इन जैसे अन्य कई युवाओं का पंच एवं सरपंच पद पर चुना जाना नए खून में जनता के भरोसे का प्रतीक है। बडगाम जिले की कारपुरा ग्राम पंचायत में पंच की उम्मीदवार 45 वर्षीय हसीना की निर्मम हत्या की वारदात पर न सिर्फ ग्रामवासी और प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार 65 वर्षीय तेजा अत्यंत दुखी हैं, बल्कि निकटवर्ती क्षेत्रों में गहरा क्षोभ है। उनकी हत्या करने वाले चाहते थे कि वह चुनावी दौड़ से हट जाए। वह गरीब विधवा थीं और चाहतीं तो अपनी उम्मीदवारी वापिस ले सकती थीं, पर वह झुकी नहीं। हसीना की हिम्मत ने जनता को निडर रहकर जीने और अपना कार्य करने का सबक दिया है।

कश्मीर की जनता अब राजनीतिक रूप से अधिक सजग है और तेजी से विकास की इच्छुक है। बारामुला जिले के एक पंचायत क्षेत्र में 100 प्रतिशत

मतदान होना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। प्रशासन को चाहिए कि वह इन 34000 नव–निर्वाचित सरपंचों और बाद में चुने जाने वाले ब्लॉक पंचायत के प्रमुखों और जिला पंचायतों के अध्यक्षों को समुचित प्रशिक्षण उपलब्ध कराए ताकि वे अपने अधिकारों एवं कामकाज के कर्तव्य के बारे में अच्छी तरह परिचित रहें। दूसरी बात, पंचायतों और उनके प्रतिनिधियों को अधिक कार्य–विषय एवं अधिकार प्रदान किए जाएं ताकि वे असरदार ढंग से कार्य कर सकें। 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देते हुए उन्हें अधिक अधिकार संपन्न बनाने पर जोर दिया गया, जिससे इसमें कोई कानूनी बाधा पैदा नहीं हो सकती। तीसरी बात, केंद्र और राज्य सरकार मिल–जुलकर राज्य में अनुकूल माहौल पैदा करें ताकि पंचायती राज संस्थाएं असरदार ढंग से विकास कार्यों को अंजाम दे सकें और जनता की खुशहाली सुनिश्चित हो। जाहिर है 1989 से हिंसा और आतंक के दौर से गुजर रहे कश्मीर में अब नई आशाएं और उम्मीदें जगी हैं। यह वक्त राजनीतिक दांव–पेंच खेलने का नहीं, बल्कि शांति एवं विकास को आगे बढ़ाने का है। यदि पंचायती राज संस्थाएं और उनके प्रतिनिधि अधिक अधिकार–संपन्न बनते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं कि लंबे समय से अशांति की मार झेल रहे इस राज्य में शांति और विकास की बयार बहेगी।

साभार : संपादकीय, पंचायती राज अपडेट

आशा ने जगाई आशा

Source:http://www.thehindu.com/news/states/other-states/article2006690.ece

कश्मीर के पंचायत चुनाव में एक पंडित महिला का जीतना एक महत्त्वपूर्ण घटना है। यह आम कश्मीरियों के मानस में आ रहे बदलाव का सूचक है, इसे देश को ही नहीं पूरी दुनिया को समझ लेना चाहिए। बारामूला जिले के एक मुस्लिम बहुल गांव वुसान में आशा पंडित ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी एक मुस्लिम महिला सारवा बेगम को 11 मतों से हराया। उस गांव में केवल पांच पंडित परिवार बचे हैं। वुसान के लोगों ने धर्म और समुदाय के आधार पर नहीं, बल्कि योग्यता के आधार पर वोट दिया। उन्हें उम्मीद है कि आशा पंडित उनके गांव की तरक्की के लिए बेहतर काम कर सकती हैं। उन्होंने अपना फैसला सुनाते समय सिर्फ अपने गांव की भलाई के बारे में सोचा। अपनी स्थानीय समस्याओं पर ध्यान दिया। और कश्मीर के नाम पर अपनी सियासी दुकान चलाने वाले अलगाववादियों के नारों, नसीहतों और धमकियों को साफ नकार दिया। पिछले कुछ वर्षों में कश्मीरी जनता में यह समझ बढ़ी है कि राजनीतिक प्रक्रिया से अलग रहकर उसने अपना ही नुकसान किया है, इसीलिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रहने के बजाय उसमें शामिल होकर अपना हक हासिल किया जाए तभी उसकी हालत बदलेगी। अब वे समझने लगे हैं कि सुरक्षा बलों की किसी ज्यादती का विरोध करने का अर्थ राष्ट्र–राज्य के खिलाफ खड़ा होना नहीं है। जनता अपने अधिकारों के लिए राज्य और केंद्र सरकार से लड़ना जरूर चाहती है, लेकिन जनतांत्रिक व्यवस्था के दायरे से बाहर जाकर नहीं। इधर कश्मीर की नई पीढ़ी का एक्सपोज़र भी देश और दुनिया से लगातार बढ़ा है। वह भी देश के और लोगों की तरह आगे बढ़ना चाहती है और जीवन की सहूलियतें हासिल करना चाहती है। पर यह तभी संभव है जब डिवेलपमेंट प्रोसेस को बढ़ावा मिले। और इसके लिए जरूरी है जनतांत्रिक संस्थाओं को

मजबूत बनाना। इसमें कोई दो मत नहीं कि पिछली कुछ सरकारों ने अपने कामकाज के जरिए उनमें यह उम्मीद बढ़ाई है। यही वजह है कि लोकसभा, विधानसभा और अब पंचायत चुनावों में जनता ने काफी बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया। पंचायत चुनावों में तो कहीं–कहीं 80 से 85 प्रतिशत तक वोट पड़े। आतंकवादी घटनाओं पर नियंत्रण से गांवों के सामाजिक जीवन में भी स्थिरता आई है और लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है। ज्यों–ज्यों विकास का मुद्दा सामने आया है, सांप्रदायिक विभाजन शिथिल पड़ा है और भय तथा संशय की कई दीवारें टूटी हैं। यह प्रक्रिया तभी मजबूत होगी, जब सरकार जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करे और जनता को हर दृष्टि से सक्षम बनाये। जनता के विश्वास की रक्षा होगी तो अलगाववाद अपने आप कमजोर होगा।

नवभारत टाइम्स से साभार

ब्रिटेन से आया एमबीए सरपंच

कुछ दिन पहले एक नाम सुना था, छवि राजावत। 31 साल की छवि जयपुर से 60 किलोमीटर दूर सोढा नाम के गांव की सरपंच हैं। वे मार्च में यूएन में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गई थीं और धूम मचाकर लौटीं। ऐसे ही युवा सरपंच की सूची में गुरुमीत बाजवा का नाम भी शामिल है।

गांव का नाम कंग है और यह भारत–पाकिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ है। केवल 27 साल की उम्र में गुरुमीत इस गांव के सरपंच बन गए हैं। 2008 में भारत लौटे बाजवा ने ब्रिटेन के डर्बीशर से एमबीए की डिग्री ली है। इलाके के प्रभावशाली परिवार से संबंध रखने वाले नए सरपंच के पिता त्रिलोक सिंह बाजवा राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। इस समय वे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के वरिष्ठ नेता हैं। 27 मई को कंग गांव के पंचायत चुनाव का फैसला आया, जिसमें गुरुमीत बहुमत से जीते।

गुरुमीत के अनुसार "मैं चाहूंगा कि बॉर्डर के नजदीकी इलाकों में रहने वाले लोगों को नौकरियों और प्रोफेशनल कॉलेजों में रिजर्वेशन मिले, जैसा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रहने वाले लोगों को मिलता है। मेरा उद्देश्य सभी वर्ग के लोगों का सामाजिक स्तर उठाना और उन्हें न्याय दिलाना है।"कंग की आबादी सिखों और गैर–सिखों का मिला–जुला रूप है, जिनमें ज्यादातर जाट हैं। इस गांव की प्रमुख समस्याओं में खेतों में सिंचाई के लिए पानी की कमी, पानी और जमीन को लेकर अक्सर पैदा होने वाले विवाद हैं। जब कभी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है, तो इस गांव के बाशिंदों को दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

नवभारत टाइम्स से साभार

महिला राजनीतिक सशक्तीकरण दिवस

इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा 25 और 26 अप्रैल, 2011 को 18वें महिला राजनीतिक सशक्तीकरण दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस बार की चर्चा "पंचायतें, महिलाएं और स्वच्छ पेयजल" विषय पर केंद्रित थी। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री अगाथा संगमा ने कहा कि जल प्रबंधन में महिलाएं प्रभावशाली भूमिका अदा कर सकती हैं, क्योंकि घर–परिवार में जल संबंधी जरूरतों की वे ही देखभाल करती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि महिलाएं बदलाव की असरदार एजेंट होती हैं, जिसके लिए उन्हें समुचित अवसर दिलाने होंगे। ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों और नीति निर्धारण प्रक्रिया में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाए, जिससे जल प्रबंधन की योजनाओं पर तेजी लाई जा सके। इस समारोह में देश के 23 राज्यों की लगभग 550 महिला पंचायत प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

श्री अगाथा ने इंस्टीट्यूट की ओर से वर्ष 2010 के लिए अरुणाचल में चैंगलैंग जिला परिषद् की अध्यक्ष जुनपो जुगली और राजस्थान में राजसमंद जिले की विजयपुरा ग्राम पंचायत की सरपंच रुक्मणी देवी साल्वी को विशिष्ट महिला प्रतिनिधि पुरस्कार देकर सम्मानित किया उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था से ही देश में सुशासन संभव है और इसके लिए इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना बेहद जरूरी है। उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि जल प्रबंधन में दक्षिणी राज्यों ने अच्छा काम किया है और बिहार में भी इसके अच्छे परिणाम आने शुरू हुए हैं। श्री अगाथा ने कहा कि अनेक महिला पंचायत प्रतिनिधियों ने जल प्रबंधन में शानदार कामयाबी का इतिहास रचा है और उससे अन्य प्रतिनिधि सबक लें।

गेस्ट ऑफ ऑनर यूएन रेजीडेंट प्रतिनिधि पेटिरिस काइली–बिजोत ने कहा कि स्त्री–पुरुष समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान में है और यह महिला सशक्तीकरण का ही एक अंग है। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वच्छ पेयजल के प्रबंधन में महिलाओं को समुचित अवसर देने पर अधिक सकारात्मक नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। यूएन वूमेन की क्षेत्रीय कार्यक्रम निदेशक ऐन स्टनहेमर ने महिला पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि आप में से जिन लोगों ने उल्लेखनीय सफलताएं पाई हैं, वे आसान नहीं थीं। आप इस कार्यक्रम में अकेली नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम आपके साथ है। इसके पहले इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के अध्यक्ष डॉ. जॉर्ज मैथ्यू ने सभी अतिथियों और महिला पंचायत प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमें स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी जरूरतों पर प्राथमिकता के आधार पर बल देना होगा। समारोह में 1999–2010 के महिला पंचायत प्रतिनिधि पुरस्कारों के बारे में एक फिल्म प्रदर्शित की गई, जिसमें पुरस्कार विजेताओं की उपलब्धियों के बारे में प्रकाश डाला गया।

भोजन के बाद हुए पहले सत्र में पंचायत प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने जल प्रबंधन की चुनौतियों एवं महिला पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की। इस सत्र की अध्यक्षता हंगर प्रोजेक्ट, भारत की कंट्री डायरेक्टर रीता सरीन ने की। इस सत्र की वक्ताओं में सिकोडिकोन, राजस्थान की सह निदेशक मंजु जोशी, सोडा ग्राम पंचायत, राजस्थान की सरपंच छवि राजावत, सॉल्यूशन एक्सचेंज, यूएनडीपी के रिसोर्स पर्सन जॉय एलामन और फतेहाबाद जिला परिषद्, हरियाणा के पूर्व सदस्य कृष्ण स्वरूप गोरखपुरिया शामिल थे। दूसरे सत्र में चीन से आई महिला प्रोफेसर वू चिंग ने “महिलाओं को वैश्विक नागरिक बनने की तैयारी” विषय पर अपने विचार रखे। प्रोफेसर चिंग ने कहा कि महिलाओं को विकास के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए, क्योंकि महिलाएं इस दुनिया में प्रेम और विश्वास का बीज होती हैं। इसीलिए यदि महिलाएं विकास करेंगी तो ये दुनिया प्रेम और संवेदनाओं से भर जाएगी। तीसरे सत्र में पंचायतों में महिलाएं : चुनौतियों से मुकाबला विषय पर बातचीत की गई। इस सत्र की अध्यक्षता सेंटर फॉर वूमेन डेवलपमेंट स्टडीज़ की निदेशक मेरी जॉन ने की। वक्ता थीं – यूएनडीपी भारत की कंट्री डायरेक्टर कैटलिन विज़न। इसमें महिला पंचायत प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने जल प्रबंधन की चुनौतियों एवं महिला पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की।

समारोह के दूसरे दिन गांव में सुरक्षित पेयजल योजनाएं – पहल एवं सफल गाथाएं, दूषित पानी का महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव और पानी की गुणवत्ता तथा जल सुरक्षा योजना में पंचायतों की भूमिका पर दो सत्र हुए। इनमें वाटर एड की इंदिरा खुराना, जागोरी की सरिता बलूनी, यूएन वूमेन की सुषमा कपूर, यूनिसेफ की नित्या जेकब, सामाजिक कार्यकर्ता भारत डोगरा आदि ने विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। सभी विशेषज्ञ इस बात पर एकमत थे कि जल तक जनता की पहुंच बढ़ानी ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्वच्छ पेयजल की सप्लाई भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। महिला प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार प्रकट किए। योजना आयोग की सदस्य सुश्री सईदा हमीद ने समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना(2012–2017)का दस्तावेज अंग्रेज़ी हिंदी दोनों में प्रकाशित किया जाएगा, ताकि अधिकतम लोग योजनाओं के बारे में जान सकें। उन्होंने पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे इसे अवश्य पढ़ें और उसके आधार पर अपने क्षेत्र के विकास की सरकार से मांग करें, क्योंकि इस दस्तावेज में प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री के

हस्ताक्षर होंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत महिला प्रतिनिधि अपने अधिकारों को सही ढंग से पहचानें और सरकार के सामने अपनी मांगें रखें। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में भारतीय संविधान में दिए गए जीवन जीने के अधिकार का वास्तविक अर्थ स्पष्ट किया है। कोर्ट के अनुसार जीने के अधिकार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमारियों के इलाज, पानी आदि के लिए अधिकार भी जुड़े हैं।

अतः इन बातों को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग तैयारी कर रहा है, जिसकी तस्वीर आप बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज मे देखेंगे।

उन्होंने कहा कि विकास का कोई एक फार्मूला पूरे भारत पर लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि यहां विभिन्न प्रकार की विविधतायें हैं। इसीलिए पंचायती राज संस्थायें अपने क्षेत्र–विशेष के अनुसार योजनाएं बनाएं और उन्हें तार्किक परिणति तक पहुंचाएं। तभी समावेशी विकास का लक्ष्य हासिल होगा। गिल्ड ऑफ सर्विस की अध्यक्ष मोहिनी गिरी ने महिला पंचायत प्रतिनिधियों से अपील की कि वे जनता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनायें। इसके लिए उन्होंने महिला पंचायत प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करने पर जोर दिया।

पंचायती राज अपडेट से साभार

कार्यक्रम और योजनाओं पर असरदार ढंग से अमल जरूरी : कैटलिन विज़ेन

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की कंट्री डायरेक्टर विज़ेन ने कहा है कि भारत में स्थानीय सरकार के स्तर पर आमतौर पर कमजोर क्षमता के कारण सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य (एमजीडी) न्यायसंगत ढंग से पाने में मुश्किलें आ रही हैं। इसका नतीजा कार्यक्रमों, योजनाओं और सेवाओं पर कमजोर ढंग से अमल के रूप में सामने आया है। यह एक प्रमुख चुनौती है, जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यूएनडीपी इन्हीं मसलों पर ध्यान देने के उद्देश्य से योजना आयोग और राज्य सरकारों को समर्थन दे रहा है। उन्होंने यह बात 10 जनवरी 2011 को "इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में रिपोर्ट ऑन द कॉन्फ्रेंस ऑन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग मेथडालॉजी एंड एक्शन, 28–29 अगस्त 2009, कोल्लम केरल" का विमोचन करते हुए कही। उन्होंने बताया कि हमारा समर्थन स्थानीय शासन की क्षमता निर्माण में निपुणताओं के विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि उन ढांचों पर भी ध्यान देते हैं, जिनका स्थानीय शासन द्वारा उपयोग किया जाता है। क्षमता से हमारा मतलब अमल के लिए निपुणताएं, संसाधन, सत्ता और प्रेरणा है। केरल इसका सफल उदाहरण है, जहां राज्य में व्यापक परिभाषा के अंतर्गत क्षमता विकास पर जोर दिया। भारत के उत्तरोत्तर संविधान संशोधनों और नीतियों का उद्देश्य भी यही है। आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के लिए पंचायतों द्वारा योजनाएं बनाने के वैधानिक कार्यों और विकास से जुड़ी योजनाओं के सुदृढ़ीकरण के योजना आयोग के अधिदेश के बावजूद इन संवैधानिक प्रावधानों पर कमजोर ढंग से अमल हो रहा है, जिसके कई कारण हैं। इसमें सफल मॉडल का अभाव और विभिन्न स्टेकहोल्डरों की कमजोर क्षमता प्रमुख है। भारत के विकास हलकों में केरल के कोल्लम मॉडल ने लोकप्रियता पाई है और योजना आयोग ने भी इसकी पद्धतियों को उपयोगी मानते हुए अन्य जिलों को इन्हें अपनाने की सलाह दी है। यह किसी से छिपा नहीं है कि स्थानीय सरकार के सबसे निचले स्तर पर फंड्स के हस्तांतरण के बिना विकेंद्रीकरण और विकेंद्रित योजना बेमानी है। केरल सरकार ने स्थानीय सरकारों को वित्तीय संसाधन हस्तांतरित किए हैं। वहां 1996 में 50 करोड़ रुपए का आवंटन पाने वाली स्थानीय सरकारों को 2010–11 में लगभग 3,000 करोड़ रुपए का विकास फंड मिला। केरल की वार्षिक योजनाओं में स्थानीय सरकारों की जरूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर संसाधनों के उपयोग की योजना की स्वायत्तता प्रतिबिंबित होती है। राज्य में लगभग 25,000 की विशाल आबादी वाली ग्राम सभाओं ने गुणवत्तापरक समावेशी योजनाएं विकसित करने में अद्भुत सफलता पाई है।

केरल से बहुत कुछ सीखा जा सकता है और इस दृष्टि से कोल्लम जिले पर उपरोक्त पुस्तक अत्यंत उपयोगी है। यूएनडीपी भारत में विकेंद्रित जिला नियोजन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए योजना आयोग, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय और अन्य पंचायतों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। जिला योजना में यूएनडीपी की भागीदारी का उद्देश्य स्थानीय सरकार के स्तर पर सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की उपलब्धियों को समर्थन देना है। इन लक्ष्यों के पाने की समय सीमा 2015 तक है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर अच्छी है, पर गरीबी और भुखमरी दूर करना तथा मानव विकास को आगे बढ़ाने के लिए काफी–कुछ करना अभी बाकी है।

राज्य समाचार

मध्य प्रदेश : पंचायतें जुड़ेंगी ई–नेटवर्क से

अगले पांच साल में मध्य प्रदेश की पंचायतों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। ऐसा केंद्रीय वित्त आयोग की इच्छा के अनुरूप किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से पंचायतों के सचिवों और सहायकों के लिए कंप्यूटर में डिप्लोमा भी अनिवार्य किया जा रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सूत्रों के अनुसार केंद्रीय वित्त आयोग चाहता है कि देश की तमाम पंचायतों का कंप्यूटरीकरण होना चाहिए। इसी के अनुरूप मध्य प्रदेश सरकार ने यह लक्ष्य तय किया है।

पहले चरण में पंचायत भवनों में कंप्यूटर कक्ष बनाने का काम किया जाएगा। शुरू में तीन हजार पंचायतों में ये कक्ष बनाए जा रहे हैं। कक्ष निर्माण के लिए दो–दो लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए अभी राशि का प्रावधान तय नहीं किया गया है। इसके लिए राज्य को वित्त आयोग से भी राशि मिलने की उम्मीद की जा रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने 'दैनिक भास्कर' को बताया कि वित्त आयोग ने सभी राज्यों से पंचायतों के कंप्यूटरीकरण के कार्य को प्राथमिकता देने को कहा है, लेकिन इसमें मध्य प्रदेश सबसे आगे है। उन्होंने बताया कि शुरुआती दिक्कत पंचायतों में काम करने वाले दक्ष लोगों की कमी को लेकर होगी। ऐसे में यह तय किया गया है कि भविष्य में पंचायतों के सचिव और सहायकों के तौर पर उन्हीं लोगों की भर्ती की जाएगी, जिनके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा हो। वर्तमान सचिवों को भी कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में पंचायत सर्विस का कैडर बनाने का भी प्रस्ताव दिया है। राज्य सरकार इस पर भी काम कर रही है। इसका उद्देश्य भी पंचायतों की कार्यप्रणाली को ऐसे कुशल लोगों के हाथों में सौंपना है जो आधुनिक तकनीकों से परिचित हों।

गोवा : किर्लापल–धबल पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार

संगेग तालुक में किर्लापल–धबल की ग्राम पंचायत को राष्ट्र स्तरीय 'गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2011' से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस समारोह में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सरपंच रमा गांओकर को 10 लाख रुपए का इनाम और एक प्रमाण पत्र दिया। पंचायत निदेशक मेनिनो डी'सूजा ने बताया कि पहली बार राज्य की किसी ग्राम पंचायत ने नियमित रूप से ग्राम सभा की बैठकें करवाने के लिए राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार जीता है। डी'सूजा ने कहा कि इस पुरस्कार के रूप में केंद्र सरकार ने किर्लापल–धबल पंचायत के आर्थिक विकास में स्थानीय समुदाय को जमीनी स्तर पर शामिल करने और ग्राम सभा के लिए सामाजिक अंकेक्षण करवाने के प्रयासों को चिन्हित किया है। पुरस्कार में मिले 10 लाख रुपए पुरस्कृत पंचायत द्वारा जन प्रयोजनों जैसे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षित पेयजल, जन–सुविधायें और ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं जैसी इन सेवाओं में खर्च करना होगा।

महिलाओं को मिलेगा 50 प्रतिशत आरक्षण :

राज्य विधानसभा ने 7 अप्रैल को उड़ीसा पंचायत कानून (संशोधन) प्रस्ताव, 2011 मंजूर कर लिया है। इस संशोधन के लागू होने के बाद पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण 33 प्रतिशत से

बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। इस आरक्षण के लागू होने के बाद पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का हिस्सा अपने पुरुष भागीदारों के बराबर हो जाएगा।

http://balaramranasingh.blogspot.com/201 1/07/women-empowerment-in-orissa.html

राष्ट्रीय समाचार

विकेंद्रीकरण लाने के लिए लंबा रास्ता तय करना होगा : मनमोहन सिंह

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि स्वशासन के विचार को कानूनी मान्यता मिल गई है, लेकिन विकेंद्रीकरण लाने के लिए अभी काफी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। उन्होंने यह बात नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 24 अप्रैल 2011, को आयोजित पंचायत दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने हाल ही में झारखंड और जम्मू–कश्मीर में हुए पंचायत चुनावों के बारे में कहा कि इन दोनों राज्यों में 70–80 प्रतिशत मतदान होना यह दर्शाता है कि लोग अब अपने भविष्य का फैसला खुद करना चाहते हैं।

विभिन्न राज्यों से आए मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री और पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि ग्राम सभाओं के पास सभी योजनाओं का सामाजिक ऑडिट करने का अधिकार होना चाहिए। ग्राम सभाओं की मनरेगा की निगरानी में विशेष भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई विकल्पों पर विचार करने की आवश्यकता है। ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित आधार पर होनी चाहिए, ताकि वे अपने विचार रख सकें। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य स्वशासन है जो लोकतंत्र का आखिरी चरण है, और इसके लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी ने पंचायत सशक्तीकरण और जवाबदेही प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों केरल, कर्नाटक, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा को वार्षिक पुरस्कार प्रदान किए।

उड़ीसा : आदर्श ई–पंचायत प्रणाली के लिए प्रथम पुरस्कार

केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने उड़ीसा राज्य पंचायती राज विभाग को सूचित किया है कि उसने राज्य पंचायती राज विभाग को उसकी पंचायतों के लिए आदर्श बही–खाता व्यवस्था और प्रिया सॉफ्ट के सफल क्रियान्वयन के लिए पुरस्कृत करने का फैसला लिया है। पुरस्कार में 50 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति–पत्र दिया जाएगा। इस सिलसिले में महाराष्ट्र और त्रिपुरा ने दूसरा तथा पंजाब और असम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है।

सभी समाचार पं.रा.अपडेट से साभार

ISST
आई.एस.एस.टी.,
अपर ग्राउंड फ्लोर, कोर 6–ए, इंडिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003 द्वारा प्रकाशित
संयोजन : मंजुश्री मिश्र, साज–सज्जा : दीपा मेहरा
ई–मेल : isstdel@isst-india.org
वेबसाइट : www.isst-india.org
फोन : 91-11-47682222, 47682234